उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग, संख्या—2044/ v / आ0—2013—51(आ0) / 13 देहरादून दिनांकः 3/ दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा—5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विनियमित क्षेत्रों हेतु एकीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 प्रख्यापित किए जाने हेतु अधिसूचना संख्या—2012/V—2011—55(आ0)/2006—टीसी दिनांक 17—11—2011 की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2— राज्य के एकीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 में सर्विस अपार्टमेंट हेतु मानक निर्धारित न होने के कारण भवन मानचित्र स्वीकृति में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 में सर्विस अपार्टमेंट हेतु निम्नानुसार बॉयलॉज अंगीकृत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

सर्विस अपार्टमेंट्स हेतु अपेक्षाएं

प्रयोजन — सर्विस अपार्टमेंट्स पूर्णतया एवं सैल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेंट्स होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोईबर) होगी तथा जो अल्प अविध की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

अन्य अपेक्षाएं -

 होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनों अथवा इनके परिसरों में कुल अनुमन्य एफ०ए०आर० का अधिकतम 20 एफ०ए०आर० सर्विस अपार्टमेंट्स हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

 व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेंट्स न्यूनतम
1000 वर्गमी० क्षेत्रफल में बनाये जा सकते हैं। इस हेतु व्यवसायिक भू-उपयोग में निर्धारित भू-आच्छादन, एफ०ए०आर० व सेटबैक अनुमन्य होगे।

उ. पृथक से नियोजित किये जाने वाले सर्विस अपार्टमेंट्स के अन्तर्गत कुल तल का क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल कार्यालय, कान्फ्रेन्स सुविधायें, गेस्ट रूम तथा सर्विस शाप्स हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

पार्किंग 100 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र या उसके अंश पर 1.5ECS

3— भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे ।

> (एम०एच० खान) प्रमुख सचिव।

संख्या-२०५५/v/आ0-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड ।

(3) समस्त जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।

(4) वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

(5) गार्डबुक् एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः यथोक्त ।